

2017/00035

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 37/2017

प्रार्थी

श्री गणेश चेरीटेबल ट्रस्ट
जसोल जरिये रिखबचन्द पुत्र
मुल्तानमल बागरेचा ट्रस्टी
निवासी जसोल तहसील,
पचपदरा

बनाम्

अप्रार्थी

1. श्री रघुवीर महाराज निवासी
जसोल रामद्वारा हाल मुरली
मनोहर धोरा भीनासर,
कोतवाली बीकानेर
2. विकास अधिकारी पंचायत
समिति, बालोतरा

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध
आदेश दिनांक 18.08.2017/21.08.2017 जो अपील संख्या 01/2017 में
विकास अधिकारी पंचायत समिति, बालोतरा द्वारा पारित किया गया।

उपस्थित:- 1. श्री मुकेश जैन अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री बांकाराम चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 02 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 14.02.2018

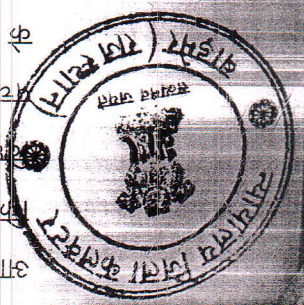
1. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी-रघुवीर महाराज अध्यक्ष सार्वजनिक रामद्वारा जसोल ने एक आवेदन पत्र दिनांक 09.05.2017 को विकास अधिकारी पंचायत समिति बालोतरा के समक्ष इस आशय का पेश किया कि ग्राम जसोल में रामद्वारा की सार्वजनिक पट्टा सुद भूमि पर ईश्वरचन्द पुत्र नरसीगदास ओसवाल निवासी जसोल व महावीचन्द पुत्र ईश्वरचन्द ओसवाल निवासी जसोल को सरपंच ग्राम पंचायत जसोल द्वारा दिनांक 12.05.2001 को स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसे निरस्त किया जाए। इस पर पंचायत समिति बालोतरा की प्रशासन एवं स्थापना समिति ने अपील संख्या 01/2017 दर्ज कर दिनांक 18.08.2017 की बैठक में बाद जाँच एवं सुनवाई ग्राम पंचायत जसोल द्वारा दिनांक 12.05.2001 को जारी स्वामित्व का प्रमाण पत्र निरस्त करने का निर्णय सर्व सम्मति से पारित किया गया। इस निर्णय की पालना में विकास अधिकारी पंचायत समिति बालोतरा ने आदेश दिनांक 21.08.2017 द्वारा ग्राम पंचायत जसोल प्रमाण पत्र संख्या 02 दिनांक 12.05.2001 को अपास्त करने का आदेश पारित किया गया। इन आदेशों से असंतुष्ट होकर प्रार्थी ने यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किया एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति बालोतरा से रिकॉर्ड तलब किया।



जिला कलक्टर
बाड़मेर

बाइल
लिना कलक्टर

इसने दोनों पक्षों की बहस सुनी। अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता ने लिखित बहस भी पेश की।
 प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि ग्राम जसोल की आबादी भूमि में एक आवासीय
 जायदाद का पट्टा संख्या 30 दिनांक 01.11.1960 को गांव के मुख्यान के नाम से रामहर के
 तैयें जारी किया जाना बताया है रामहर का कोई जरिया नहीं होने एवं कुछ
 निर्माण करवाना आवश्यक होने से इंशुरचन्द पुत्र नरसिंहादास निवासी जसोल ने निर्माण हेतु
 7000/- की राशि दी जिससे टुकानों का निर्माण कराया गया व इसके बदले मुख्यान द्वारा
 कुल 1020.03 वर्ग फीट भूमि उसी समय इंशुरचन्द को दे दी गई जिसके कुछ भाग पर निर्माण
 कराया व निर्मित भाग में बिजली, पानी की सुविधा प्राप्त करने हेतु स्वामित्व प्रमाण पत्र की
 आवश्यकता होने से उनके द्वारा वर्ष 1981 में एक प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत
 किया गया। जिस पर ग्राम पंचायत जसोल द्वारा इंशुरचन्द पुत्र नरसिंहादास के पक्ष में पानी एवं
 विद्युत कनेक्शन हेतु प्रमाण-पत्र दिनांक 18.12.1981 को जारी किया गया। तत्पश्चात् ग्राम
 पंचायत जसोल द्वारा इंशुरचन्द पुत्र नरसिंहादास एच.यू.एफ. के कर्ता महावीरचन्द पुत्र इंशुरचन्द
 के पक्ष में स्वामित्व प्रमाण पत्र संख्या 02 दिनांक 12.05.2001 को जारी किया गया। इस
 जायदाद का हस्तांतरण इंशुरचन्द पुत्र नरसिंहादास द्वारा दिनांक 14.05.2001 को श्री गणेश
 चरितबल ट्रस्ट को जरिये रजिस्टर्ड विलेख से किया है जो बेवाननामा कर्ता सयुक्त हिन्दु
 परिवार के कर्ता की हैसियत से महावीरचन्द पुत्र इंशुरचन्द द्वारा प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित
 किया गया, जिसके फलस्वरूप प्रार्थी इस जायदाद पर कालिज मालिक बन गया। इस पर एक
 बड़ा हाल एवं दो टुकानों का निर्माण प्रार्थी द्वारा कराया गया है। इसके आधार पर इंशुरचन्द
 पुत्र नरसिंहादास आसवाल निवासी जसोल व महावीरचन्द पुत्र इंशुरचन्द आसवाल निवासी
 जसोल के पक्ष में स्वामित्व का प्रमाण पत्र संख्या 02 दिनांक 12.05.2001 जारी किया गया।
 इसमें अप्रार्थी संख्या 02 रामहरा जसोल की किस्ती प्रकार की सम्पत्ति एवं स्वामित्व हासिल नहीं
 है इसके बावजूद प्रार्थी के विरुद्ध एक प्रार्थना के जरिये ग्राम पंचायत द्वारा जारी स्वामित्व
 प्रमाण पत्र निरस्त करवाया गया है, जो गलत एवं विधि विरुद्ध है। उन्होंने तर्क दिया कि ग्राम
 पंचायत द्वारा स्वामित्व प्रमाण पत्र 2001 में जारी किया गया जिसके विरुद्ध अपील 2017 में एक
 लम्बे समय बाद पेश की गई, जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है। अपील के साथ धारा 05
 मियाद अधिनियम के तहत कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया। रेस्पॉण्डेंट संख्या 01 को अपील
 पेश करने कोई अधिकार ही नहीं था, क्योंकि उनका विवादग्रस्त जायदाद से कोई सम्बन्ध ही
 नहीं है सदस्यक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 02/2006
 में स्वयं रेस्पॉण्डेंट ने विवादग्रस्त जायदाद रामहर के की नहीं मानी है। ग्राम पंचायत जसोल द्वारा
 प्रार्थी के पक्ष में जारी स्वामित्व के प्रमाण पत्र के विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा पंचायत समिति
 की स्थापना समिति के समक्ष विधिवत कोई अपील प्रस्तुत नहीं कर केवल मात्र एक प्रार्थना पत्र
 पर स्थापना समिति द्वारा कार्यवाही की गई जो अपील पेश करने की एक निष्पादित प्रक्रिया के



प्रतिकूल है। पंचायत समिति द्वारा अपील में संबंधित एवं पीड़ित पक्षकारान को पक्षकार नहीं बनाया गया और न उन्हे सुनवाई का नोटिस दिया गया है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 61 के अधीन प्रस्तुत अपील में कोई भी आदेश प्रभावित पक्षकार को सुनवाई के पश्चात् ही पारित किया जा सकता है। यह एक आज्ञापक प्रावधान है परन्तु इस प्रकरण में विधि के आज्ञापक प्रावधान की पूर्णतया अनदेखी करके आदेश पारित किया गया है। धारा 56 के तहत गठित कमेटी द्वारा ही अपील की सुनवाई की जा सकती है। विकास अधिकारी को इस मामले में अपील की सुनवाई अथवा निर्णय पारित करने के अधिकार नहीं था क्योंकि विधिवत रूप से कमेटी का गठन नहीं हुआ। इसलिये प्रार्थी की निगरानी स्वीकार कर पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना समिति द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.08.2017 व 21.08.2017 को निरस्त फरमाया जाए।

इसके जवाब मे अप्रार्थी संख्या 02 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि निगरानीकर्ता का कथल गलत है कि उक्त सम्पति का बेचान सार्वजनिक ट्रस्ट के निर्माण हेतु किया गया था प्रार्थी का यह कथन मनमर्जी से बिना किसी युक्ति संगत आधार के किया गया है प्रार्थी निगरानीकर्ता को ट्रस्ट की ओर से कभी भी सम्पति को बेचान नहीं किया गया और न बेचाननामा में उक्त सम्पति सार्वजनिक हितार्थ सार्वजनिक निर्माण कार्य ट्रस्ट के उपयोग-उपभोग हेतु रकम की आवश्यकता बताकर किया गया हो को कोई उल्लेख नहीं है सार्वजनिक ट्रस्ट की सम्पति का बेचान किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता और न ही ऐसी सम्पति को खरीद की जा सकती है जिस सम्पति के बारे में ग्राम पंचायत द्वारा स्वामित्व व प्रमाण पत्र जारी किया गया है, वह ग्राम पंचायत, जसोल के क्षेत्राधिकार का सामला नहीं होने एवं सम्पति कभी भी ग्राम पंचायत जसोल की मालिकाना की सम्पति नहीं रही है। यह सम्पति सार्वजनिक रामद्वारा ट्रस्ट वैष्णव सम्प्रदाय जसोल की सम्पति रही है और रामद्वार ट्रस्ट के नाम से ग्राम पंचायत जसोल से पट्टा संख्या 30 दिनांक 01.11.1960 को जारी किया जा चुका है जारी पट्टा आज भी प्रभावी है। इस सम्पति के सार्वजनिक ट्रस्ट के नाम पट्टा रहते हुए ग्राम पंचायत को किसी प्रकार का स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं था। उन्होंने तर्क दिया कि अप्रार्थी की सार्वजनिक रामद्वारा की सम्पति पर बिना किसी कानूनी अधिकार के प्रार्थी के पक्ष में ग्राम पंचायत जसोल द्वारा स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने पर अप्रार्थी द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति बालोतरा के समक्ष अपील के रूप में आवेदन पत्र पेश किया। जिस पर विकास अधिकारी पंचायत समिति की स्थापना समिति ने बाद जाँच एवं सुनवाई के सर्व सम्मति से स्वामित्व प्रमाण पत्र दिनांक 18.08.2017 निरस्त करने का निर्णय लिया जाकर आदेश दिनांक 21.08.2017 द्वारा निरस्त किया गया है, जो सही रूप से खारिज किया गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि ग्रामीण विकास विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ4(16) दिशा-निर्देश/विधि/प.स./2016/325 दिनांक 19.04.2017 द्वारा ग्राम पंचायत को स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा



जिला कलेक्टर
बाड़मेर

अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं करने के निर्देश दिये है। इस परिपत्र अनुसार भी विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत जसोल की ओर से जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। इसलिये प्रार्थी की निगरानी आधारहीन होने से खारिज की जाए।


5. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली एवं अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने यह निगरानी पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना समिति बालोतरा द्वारा अपील संख्या 01/2017 में पारित निर्णय दिनांक 18.08.2017 एवं विकास अधिकारी बालोतरा द्वारा इस निर्णय की पालना में जारी आदेश दिनांक 21.08.2017 को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत पेश की है। अपीलाधीन पत्रावली के अवलोकन से श्री रघुवीर महाराज अध्यक्ष सार्वजनिक रामद्वारा जसोल द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति बालोतरा को ग्राम पंचायत जसोल के ग्राम जसोल में सार्वजनिक रामद्वारा की पट्टा सुद भूमि में श्री ईश्वरचन्द पुत्र नरसिंगदास ओसवाल-जसोल व महावीरचन्द पत्र ईश्वरचन्द ओसवाल जसोल को सरपंच ग्राम पंचायत जसोल द्वारा जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र निरस्त करने के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली कायम कर ग्राम पंचायत जसोल द्वारा श्री महावीरचन्द ईश्वरचन्द एवं ईश्वरचन्द नरसिंगदास के नाम से जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र की जाँच पंचायत प्रसार अधिकारी, बालोतरा से करवाने का दिनांक 11.05.2017 को निर्णय लिया गया। पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट दिनांक 15.05.2017 में वर्ष 1958-59 में सार्वजनिक रामद्वारा के नाम ग्राम पंचायत जसोल ने पट्टा संख्या 30 जारी करना एवं रामद्वारा सार्वजनिक एवं धार्मिक आस्था का केन्द्र बताया। ग्राम पंचायत जसोल द्वारा जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत जसोल के स्व-विवेक से जारी होना और इस बाबत ग्राम पंचायत जसोल की साधरण बैठक अथवा ग्राम पंचायत की बैठक में कोई प्रस्ताव पारित नहीं होना तथा ग्राम पंचायत जसोल की कार्यालय में उपलब्ध स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रति में ओवर हैण्ड राईटिंग एवं काँछ-छांट होना बताया। स्वामित्व प्रमाण पत्र निरस्त करने के सम्बन्ध में विचार विमर्श हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति बालोतरा द्वारा दिनांक 16.06.2017 को पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना समिति की बैठक आयोजित करने की सूचना दिनांक 06.06.2017 को जारी की गयी और प्रार्थी को उक्त भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु बैठक में उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी किया गया। मगर प्रार्थी अथवा उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। तत्पश्चात् दिनांक 18.08.2017 को पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना समिति की पुनः बैठक आयोजित करने की सूचना जारी कर प्रार्थी को इसकी सूचना की प्रति भेजी गई मगर प्रार्थी अथवा उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। इस प्रकार पंचायत समिति की स्थापना समिति द्वारा ग्राम पंचायत को राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 140 से 163 तक में आबादी भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण नियमानुसार प्रक्रिया का पालन नहीं करने एवं राजस्थान पंचायती राज




अधिनियम,1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम,1996 में ग्राम पंचायत को स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का कोई प्रावधान नहीं होने के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा जारी स्वामित्व का प्रमाण पत्र संख्या 02 दिनांक 12.05.2001 को सर्व सम्मति से निरस्त करने का निर्णय दिनांक 18.08.2017 पारित किया है,वह विधि सम्मत है। प्रार्थी का यह कथन कि स्थायी समिति द्वारा निर्णय गलत एवं नियम विरुद्ध तरीके से पारित किया हैं। राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा 56 के अनुसार गठित पंचायत समिति की स्थायी समिति द्वारा सुनवाई की जायेगी। स्थायी समिति को किसी विषय पर प्रस्ताव पारित करने से बैठक का प्रारम्भ एवं उसकी वैधानिकता/गणपूर्ति अर्थात् कोरम पर निर्भर करती है। गणपूर्ति के लिये उसके सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई से अन्धून बहुमत से समर्थित होना चाहिये। पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना समिति की बैठक दिनांक 18.08.2017 मे 05 सदस्यों की उपस्थिति दर्शायी गयी है। निर्णय पारित करने से पूर्व स्थापना समिति का कोरम पूरा होने के उपरान्त पारित किया गया है। ग्राम पंचायत जसोल द्वारा दिनांक 12.05.2001. को जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र संख्या 02 को प्रशासन व स्थापना समिति की बैठक में सर्व सम्मति से निरस्त करने का निर्णय दिनांक 18.08.2017 एवं जारी आदेश दिनांक 21.08.2017 पारित किया गया है इसमें कोई वैधानिक त्रुटि एवं अनियमितता प्रतीत नहीं हुई है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है।




(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलेक्टर, बाड़मेर
जिला कलेक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 14.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


जिला कलेक्टर, बाड़मेर
जिला कलेक्टर
बाड़मेर